

IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद के पास, जब आपातकाल की उद्घोषणा संचलन में हो, राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।
2. राष्ट्रपति, संसद की सहमति से, किसी भी मामले के संबंध में एक राज्य सरकार को कुछ कार्य सौंप सकता है, जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (b)

संसद के पास, जब आपातकाल की उद्घोषणा संचलन में हो, राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से किसी भी विषय के संबंध में सरकार या उसके अधिकारियों को सशर्त या बिना शर्त कार्य सौंप सकते हैं, जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी केंद्रशासित प्रदेश (राज्य शामिल नहीं हैं) के मामले में, संसद के पास राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है।
2. संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी कर को लागू करने वाले किसी भी कानून को बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (c)

संसद के पास भारत के केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, इस बात के बावजूद कि इस मामले को राज्य सूची में शामिल किया गया है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी कर को लागू करने वाले किसी भी कानून को बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है। (संसद के पास अवशिष्ट कर लगाने की विशेष शक्तियां हैं)

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

1. भारत सरकार ऐसे क्षेत्र की सरकार में निहित न्यायिक कार्यों के लिए किसी भी क्षेत्र की सरकार (भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना) के साथ समझौता कर सकती है।
2. मिजोरम के राज्यपाल भी निर्देश जारी कर कह सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य के एक आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (a)

भारत सरकार ऐसे क्षेत्र की सरकार में निहित किसी भी कार्यकारी, विधायी या न्यायिक कार्यों को करने के लिए भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं होने के साथ किसी भी क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता कर सकती है। लेकिन ऐसा समझौता लागू होते समय किसी कानून के अधीन प्रशासित होगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

असम के राज्यपाल निर्देश जारी कर यह कह सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य में एक आदिवासी क्षेत्र (स्वायत्त जिले) पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों (स्वायत्त जिलों) के संबंध में समान शक्ति प्राप्त है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करने की शक्ति है।
2. संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

संसद कानून द्वारा संघ सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में संसद या किसी भी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए कानून प्रदान कर सकती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

1. संसद द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर अमान्य माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन (extra-territorial operation) होगा।
2. केवल संसद वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बना सकती है, जहां अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (b)

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन (extra-territorial operation) होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद के पास वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जहां माल, या सेवाओं की आपूर्ति, या दोनों अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.6) संविधान की 5 वीं अनुसूची के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्यपाल को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र (scheduled area) घोषित करने का अधिकार है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है।
3. जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श के बाद राज्यपाल को एक अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बनाने का अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.6) Solution (c)

किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। वह इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसकी सीमा रेखा को परिवर्तित कर सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के बारे में सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है। इसमें 20 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से तीन-चौथाई राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। वह जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श के बाद एक अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम भी बना सकते हैं।

IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष के मामले में, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रबल (prevails) होता है।
2. शिक्षा आरंभ में राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय थी, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय सूची में लाया गया।
3. एक विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 3
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.7) Solution (c)

समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष के मामले में, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रबल होता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

42 वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया।

इसलिए कथन 2 गलत है।

एक विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।

इसलिए कथन 3 गलत है।

Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, प्रत्येक राज्य को नहीं।
2. अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान नीति आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को दिया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

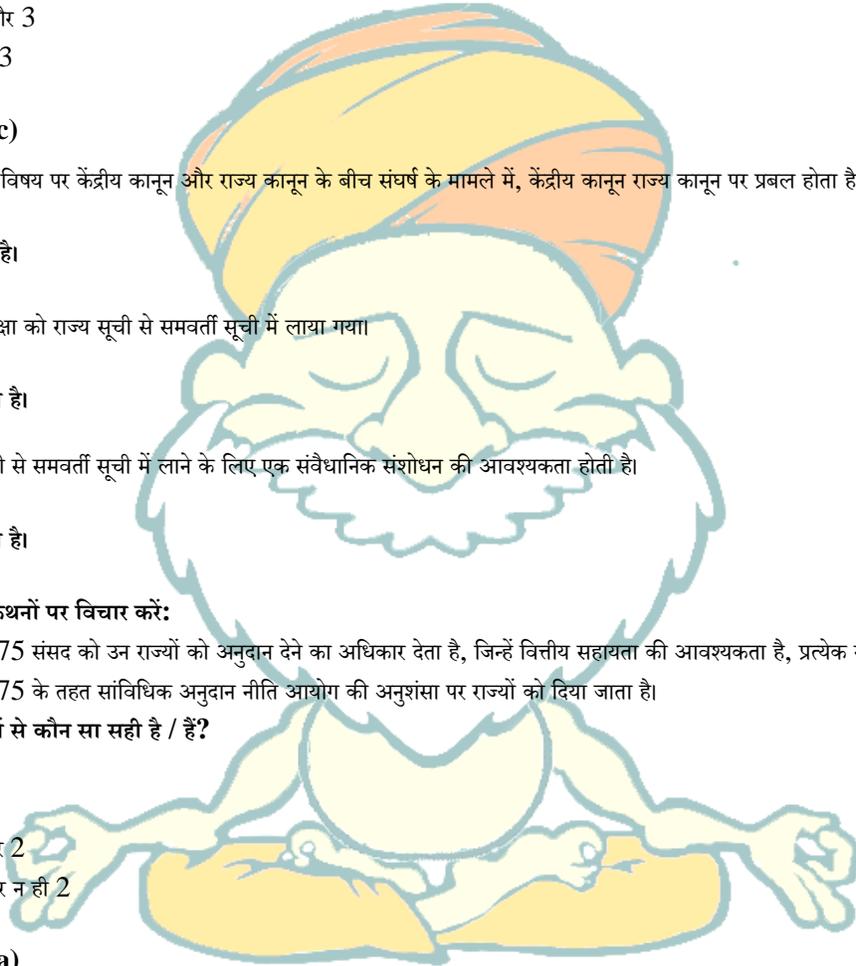
Q.8) Solution (a)

सांविधिक अनुदान (Statutory Grants): अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, प्रत्येक राज्य को नहीं। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग राशि तय की जा सकती है। ये राशि हर साल भारत के समेकित कोष पर भारत होती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत सांविधिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।



IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

Q.9) केंद्र को निम्नलिखित में से किस मामले में अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में राज्यों को निर्देश देने का अधिकार है?

1. राज्य द्वारा संचार के साधनों का निर्माण और रखरखाव।
2. राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय।
3. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का खाका और क्रियान्वयन।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q.9) Solution (d)

राज्य द्वारा संचार के साधनों (राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के) का निर्माण और रखरखाव;

राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय;

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान

राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का खाका और क्रियान्वयन।

Q.10) निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं (Federal features) माना जाता है?

1. लिखित संविधान
2. एकीकृत न्यायपालिका
3. शक्तियों का विभाजन
4. एकल संविधान
5. एकीकृत चुनावी मशीनरी

सही कूट का चयन करें:

- a) केवल 1, 2, 4 और 5
- b) केवल 1, 2, 3 और 5
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.10) Solution (c)

दोहरी राज्यव्यवस्था (Dual Polity), लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की कुछ संघीय विशेषताएं हैं।

एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान, एकीकृत चुनाव मशीनरी, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की कुछ एकल/केंद्रीय विशेषताएं हैं।

Q.1) निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक की राज्य तितली (state butterfly) माना जाता है?

- a) दक्षिणी बर्डविंग (Southern Birdwing)
- b) गोल्डन बर्डविंग (Golden Birdwing)
- c) स्ट्रीप्ड हेयरस्ट्रीक (Striped Hairstreak)
- d) गोल्डन बटरफ्लाई (Golden Butterfly)

Q.1) Solution (a)

IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

दक्षिणी बर्डविंग, जिसका वैज्ञानिक नाम *Troides minos* है, के पास 140-190 मिमी के पंख होते हैं, जिसे भारत में सबसे बड़ा तितली माना जाता था।

राज्य तितली चुनने वाला कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है।

दक्षिणी बर्डविंग को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसका रंग कर्नाटक ध्वज के रंगों से मेल खाता था।

क्या आप जानते हैं?

- गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली अब 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली बन गयी है। गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग से बड़ी है, जिसे पहले सबसे बड़ा माना जाता था।

Source: <https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/himalayan-butterfly-is-indias-largest-after-88-years/article32012652.ece>

Q.2) पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) के बारे में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें

- इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है
- यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर स्थित है
- यह एक खारे पानी (brackish water) की झील है

सही कथनों का चयन करें

- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3

Q.2) Solution (b)

पैंगोंग झील अर्थात पैंगोंग त्सो

- यह हिमालय में एक बन्द जलसम्भर झील (endorheic lake) है।
- पैंगोंग झील की लंबाई का लगभग 60% तिब्बत में स्थित है।
- हालांकि यह एक खारे पानी की झील है, लेकिन यह पूरी तरह से सर्दियों के दौरान जम जाती है।
- पैंगोंग झील के खारे पानी में बहुत निम्न सूक्ष्म वनस्पति हैं। कथित तौर पर, झील में, सिवाय क्रस्टेशियंस (crustaceans) के कोई मछली या कोई जलीय जीवन नहीं मिलते हैं।
- झील रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में जाने जाने की प्रक्रिया में है। यह कनवेंशन के तहत दक्षिण एशिया में पहली सीमा-पारीय (ट्रांस-बाउंड्री) आर्द्रभूमि होगी।

पैंगोंग झील एक विवादित क्षेत्र है। वास्तविक नियंत्रण रेखा झील से होकर गुजरती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किमी दूर झील का एक हिस्सा चीन द्वारा नियंत्रित है लेकिन भारत द्वारा दावा किया जाता है। पूर्वी छोर तिब्बत में है और भारत इस पर दावा नहीं करता है। पश्चिमी छोर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है।

Q.3) कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central sector scheme) है।
- योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2022 (2 वर्ष) तक होगी।
- यह फसल-पूर्व (pre-harvest) और कटाई के पश्चात् (post-harvest) के बुनियादी ढांचे के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

- केवल 1
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1, 2 और 3

Q.3) Solution (a)

कृषि अवसंरचना कोष

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना -कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इस योजना के बाद फसल प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक होगी।
- कृषि-उद्यमियों, स्टार्ट-अप, कृषि -तकनीकी अभिकर्ताओं और बुनियादी सुविधाओं तथा रसद सुविधाओं के लिए किसान समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि-अवसंरचना कोष के साथ है।

Source: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637221>

Q.4) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

(ऑपरेशन का नाम):: (संबद्धता)

- ऑपरेशन सद्भावना (Operation Sadbhavna): वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ तनाव में कमी लाने हेतु
- ऑपरेशन समुद्र सेतु (Operation Samudra Setu):: COVID-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा
- ऑपरेशन सुकून (Operation Sukoon):: जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में आतंकवाद-रोधी रणनीति

ऊपर दी गई कौन सी जोड़ी सही है / हैं?

- केवल 2
- केवल 3
- 1 और 2
- 1, 2 और 3

Q.4) Solution (a)

ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसे COVID-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में 05 मई 2020 को आरंभ किया गया था, 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्री मार्ग से वापस लाने के बाद सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है।

ऑपरेशन सद्भावना - सेना ने जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अनूठी मानवीय पहल की। ऑपरेशन पहल करने और राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ 'आम-जन' को फिर से एकीकृत करने के लिए आतंकवाद- रोधी रणनीति का एक हिस्सा है।

ऑपरेशन सुकून और ऑपरेशन राहत पहले पूर्व में 2006 और 2015 में क्रमशः इसी तरह के निकासी ऑपरेशन किए गए थे।

Source: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637314>

Operation Sadbhavna – Picked from India Year Book, 2020

Q.5) 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ)' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

IASbaba Integrated Revision Programme 2020 – Day 26 POLITY

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कानून संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XIV द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की।
2. इसमें यूएनएससी के स्थायी सदस्यों द्वारा नौ वर्ष के लिए चुने गए पंद्रह न्यायाधीश होते हैं

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (a)

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कानून संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XIV द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ न्यायाधीशों के पद के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। ये अंग एक साथ लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए, एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहिए। न्यायालय के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में पांच न्यायाधीशों का चुनाव होता है। यदि किसी न्यायाधीश की पद पर आसीन रहते हुए मृत्यु होती है, इस पद को पूरा करने के लिए आम तौर पर एक विशेष चुनाव में न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है।

कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते।

